



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

भास्त्राधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353] महि विलासी, शनिवार, नवम्बर 5, 1977/कार्तिक 14, 1899

No. 353] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 5, 1977/KARTIKA 14, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे इक वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi the 5th November 1977

G.S.R. 679(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:—

PROCLAMATION

Whereas, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, have received a report from the Governor of the State of Tripura and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State,
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament, and
- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—
- (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—

- so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;
- so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the Legislature of the State of the reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India,
- articles 163 and 164,
- so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State,
- article 187 and so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;
- clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174; articles 176 to 178 (both inclusive), clause (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article and articles 180 and 181,
- so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 188, 189, 193, 194, 195 and 196, article 198; clauses (3) and (4) of article 199;
- so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 208 to 211 (both inclusive); the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and
- so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved,

(iv) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the reference in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively.

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Tripura General Clauses Act, 1966 (Act of 1966), as in force in the State of Tripura, and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in the relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State

New Delhi,
The 5th November, 1977

NEELAM SANJIVA REDDY,
President.

New Delhi,
The 5th November, 1977

{No. V/11013/28/77-S&P(DV)}
T C A SRINIVASAVARADAN,
Secretary.

गृह मंज्ञालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1977

प्राप्ति निः ६, ९(अ) — राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :—

उद्घोषणा

बत. मुझे, भारत के राष्ट्रपति, नीलम सजीव रेण्डी को त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और मुझे प्राप्त इस रिपोर्ट और अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्तम हो गई है कि जिसमें कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान जिसे इसके पश्चात् “संविधान” कहा गया है के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है,

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उद्घोषणा करता हूँ कि मैं—

- (क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उम राज्य के राज्यपाल में निहित या एतद्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने हाथ में लेता हूँ,
- (ख) घोषित करता हूँ कि उक्त राज्य विधान मंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होती हैं ; और
- (ग) निम्नलिखित अनुरूपिक और परिणामिक उपबंध करता हूँ जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए मुझे आवश्यक या बांधनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात्—
 - (i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खंड (क) के आधार पर अपने हाथ में लिए गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझ उक्त राज्य के राज्यपाल के भाष्यम से कार्य करना विविध पूर्ण होगा ;
 - (ii) उस राज्य के संबंध में संविधान के निम्ननिखित उपबंधों के प्रवर्तन को एतद्वारा निम्नस्वित किया जाता है, अर्थात्—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निवेश करने से है ;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के राज्य विधान मंडल के समझ रखे जाने में है ,

अनुच्छेद 163 और 164 ;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य सरकार के कार्यों का भवियों के बीच आवंटन से है ; अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 169 के खंड (1) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प के पारित किए जाने से है ,

अनुच्छेद 174 का खंड (1) और खंड (2) का उपखंड (क) ; अनुच्छेद 175 से 178 तक जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं, अनुच्छेद 179 का खंड (ख) और (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक और अनुच्छेद 180 और 181,

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के संबलमों और भत्तो से है; अनुच्छेद 188, 189, 193, 194, 195 तथा 196; अनुच्छेद 198; अनुच्छेद 199 का खंड (3) और खंड (4) ;

अनुच्छेद 202 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के सबलमों और भत्तो से है; अनुच्छेद 208 से 211 तक जिसमें यह दोनों सम्मिलित है; अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परन्तुक और खंड (3) का परन्तुक; और

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध आपन सहित रिपोर्ट को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है

(iii) उक्त राज्य की विधान सभा एनद्डारा विधिटि की जानी है;

(iv) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी देश का ग्रथ उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निर्देश लगाया जाएगा और उसमें राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति किसी निर्देश का, जहाँ तक उसका संग्रह उसके क्रूर्यों और उसकी गतियों से है, ग्रथ जब तक कि सदर्भ में अन्यथा अरेक्षित न हो, ससद के प्रति निर्देश लगाया जाएगा, और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 में राज्य पाल और राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति निर्देश का ग्रथ अपन राष्ट्रपति और ससद या उसके सदनों के प्रति निर्देश लगाया जाएगा।

परन्तु इसमें कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक जिसमें दोनों भी सम्मिलित है, प्रृच्छेद 239 और अनुच्छेद 361 तथा वित्तीय अनुसूची के वैरा 1 से 4 तक जिसमें दोनों भी सम्मिलित हैं के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को इन खण्ड के उपबंध (1) के अधीन उस सीमा तक जहा तक वह ठीक समझे, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी ,

() राज्य के विधान मंडल के या एनद्डारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का ऐसे ग्रथ लगाया जाएगा मानों उसके गतांत इस उद्घोषणा के आधार पर ससद द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) और तिपुरा राज्य में ग्रथप्रवृत्त विपुरा साधारण खण्ड अधिनियम, 1966 (1966 का 5) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की गतियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निर्देश है, और साधारण खंड अधिनियम 1897 (1897 के 1वें) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है।

ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानों यह उस राज्य विधान मंडल का अधिनियम हो ।

नई दिल्ली ;

5 नवम्बर, 1977

नीलम संजीव रेहुरी,

राष्ट्रपति ।

[सं. 11013/28/77-एस० एड पी० (डी-5)]

नई दिल्ली ;

5 नवम्बर, 1977

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन,

सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th November 1977

G.S.R. 680(E).—The following Order by the President is published for general information:

In pursuance of sub-clause (i) of clause c) of the Proclamation issued on this the 5th day of November, 1977 by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Tripura and all the powers vested in or exercisable by the Government of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State

New Delhi,
The 5th November, 1977

New Delhi:
The 5th November, 1977

[No. V/11013/28/77-S&P(DV)]
T. C. A. SRINIVASAVARADAN,
Secretary.

आदेश

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1977

सांकेति० ६४०(अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्ननिवित अदेश मर्यादारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :

भारत के संविधान के अधीन मेरे द्वारा आज 1977 को नवम्बर के पांचवें दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) का अनुसरण करते हुए मैं इन द्वारा निर्देश देता हूँ कि लिपुरा राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रदृढ़ किए विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों, जिनको राष्ट्रपति उक्त

उद्धीषण के खण्ड (क) के प्रांत पर अपने हाथ में लिया है, राष्ट्रपति के प्रधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

मई दिल्ली ;

5 नवम्बर 1977

नीलम संजीव रेही,

राष्ट्रपति ।

[सं० 11013/28/77-एस० एंड पी० (डी-5)]

नई दिल्ली ;

5 नवम्बर, 1977

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरङ्गन,

सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977